नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 254
दि. 17.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्यार, परिवार और पहचान के बीच फंसी काजोली की जिंदगी, डिपोर्टेशन के डर से बिखरने की कगार पर एक घर

आनंद। कभी सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक साधारण दोस्ती ने प्यार का रूप लिया, फिर सीमाओं को लांघते हुए विवाह और परिवार तक पहुंची। लेकिन अब वही कहानी कानून, नागरिकता और पहचान के जटिल सवालों के बीच उलझ गई है। गुजरात के आनंद जिले से सामने आया यह मामला केवल एक महिला की कानूनी स्थिति का नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की पीड़ा का प्रतीक बन गया है, जो पिछले दस वर्षों से साथ रह रहा था और अब अचानक बिछड़ने के खतरे का सामना कर रहा है। एक ओर कानून है, जो देश की सीमाओं और नागरिकता संबंधी नियमों को सर्वोपरि मानता है, तो दूसरी ओर एक मां, उसके पति और दो छोटे बच्चों का भावनात्मक संसार है, जो टूटने की आशंका से घिरा हुआ है।

आनंद जिले के लांभवेल गांव में रहने वाले तरुण पटेल की जिंदगी करीब एक दशक पहले उस समय बदली थी, जब उनकी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बांग्लादेश की रहने वाली काजोली बेबो से हुई। शुरुआत में सामान्य बातचीत के रूप में शुरू हुआ यह परिचय धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों अलग-अलग देशों में रहते थे, लेकिन भावनात्मक निकटता इतनी बढ़ी कि उन्होंने साथ जीवन बिताने का निर्णय कर लिया।

बताया जाता है कि दोनों ने विवाह का सपना देखा, लेकिन सीमाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं के बीच यह आसान नहीं था। इसके बावजूद काजोली ने अपने प्रेम को पाने के लिए भारत आने का निर्णय लिया। वह गुजरात पहुंचीं और आनंद में तरुण पटेल के साथ रहने लगीं। बाद में उन्होंने काजल पटेल नाम अपनाया और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया। परिवार के लोगों के अनुसार विवाह के बाद उन्होंने भारतीय जीवनशैली को अपनाया, स्थानीय संस्कृति में खुद को

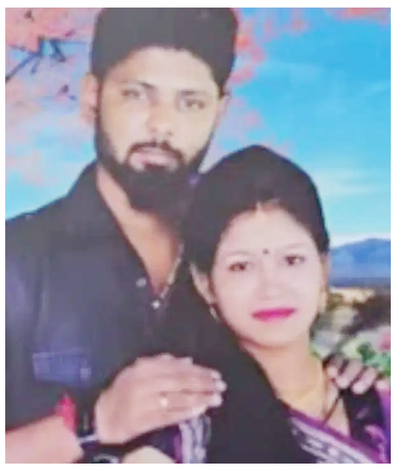

ढाला और एक सामान्य गृहिणी की तरह परिवार के साथ जीवन बिताने लगीं।

समय बीतता गया और इस दंपती के जीवन में दो बेटों का जन्म हुआ। परिवार का दायरा बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं और जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहा। गांव और आसपास के लोगों के लिए भी यह एक साधारण परिवार की तरह था। पड़ोसियों के अनुसार काजल घर-परिवार में पूरी तरह रच-बस गई थीं और बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती थीं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों पहले की उनकी पहचान एक दिन उनके वर्तमान जीवन के सामने इतनी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी।

हाल के महीनों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान काजल की पहचान और दस्तावेजों की जांच हुई। जांच में यह सामने आया कि उनके पास भारत में रहने के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत महिला आश्रय गृह भेज दिया। अब उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की खबर ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है।

काजल की हिरासत के बाद सबसे अधिक प्रभावित उनके बच्चे हुए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि छोटा बेटा अभी बहुत कम उम्र का है और अपनी मां से अलगाव को समझ भी नहीं पा रहा। वह लगातार मां को ढूंढ़ता रहता है और उनके बिना सामान्य नहीं हो पा रहा। बड़ा बेटा भी मानसिक रूप से परेशान है और बार-बार यह सवाल करता है कि उसकी मां कब घर लौटेगी। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है क्योंकि वे अचानक अपनी मां से दूर हो गए हैं।

पति तरुण पटेल भी इस पूरे घटनाक्रम से गहरे आहत दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी पिछले दस वर्षों से उनके साथ रह रही हैं, उन्होंने परिवार बसाया है, बच्चों को जन्म दिया है और भारतीय समाज का हिस्सा बनकर जीवन जिया है। उनके अनुसार यदि उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता है तो परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। तरुण का दावा है कि उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म अपनाया है और ऐसे में उन्हें बांग्लादेश भेजे जाने की स्थिति में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इस मामले ने कानूनी और मानवीय दोनों स्तरों पर बहस छेड़ दी है। एक पक्ष का मानना है कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए नागरिकता तथा आव्रजन संबंधी कानूनों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के अनुसार होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरा पक्ष यह सवाल उठा रहा है कि जब कोई व्यक्ति वर्षों से एक परिवार का हिस्सा बन चुका हो, उसके छोटे बच्चे हों और उसका पूरा जीवन उसी देश में बस गया हो, तब ऐसे मामलों में मानवीय पहलुओं को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां विवाह, नागरिकता और अवैध प्रवास से जुड़े प्रश्न एक-दूसरे से टकराते हैं। ऐसे मामलों में अदालतें और प्रशासन अक्सर कानून और मानवीय परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित देश के कानूनों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाता है।

फिलहाल काजल पटेल उर्फ काजोली बेबो का मामला केवल एक महिला के डिपोर्टेशन तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी बन चुका है, जो प्रेम, विश्वास और साथ के आधार पर खड़ा हुआ था, लेकिन अब कानूनी चुनौतियों के कारण टूटने के खतरे का सामना कर रहा है। गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा है और कई लोग परिवार के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं।

आने वाले दिनों में प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया इस मामले की दिशा तय करेगी। परिवार को उम्मीद है कि उनकी परिस्थितियों पर मानवीय दृष्टिकोण से भी विचार किया जाएगा, जबकि कानून अपना रास्ता तय करेगा। इस बीच दो मासूम बच्चों की आंखों में अपनी मां के लौट आने की उम्मीद और एक पति की अपने परिवार को बचाने की कोशिश इस पूरे मामले को केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय कहानी बना देती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे होने वाला फैसला कानून की कठोरता और मानवीय संवेदनाओं के बीच किस तरह का संतुलन स्थापित करता है।

नीट विवाद पर गरमाई सियासत, खरगे का सरकार पर हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं को लेकर देश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि परीक्षा घोटालों और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रहने के बावजूद सरकार जवाबदेही तय करने से बच रही है। खरगे ने विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार को टेलीग्राम जैसे डिजिटल मंचों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए जिनके कार्यकाल में करोड़ों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या का समाधान करने के बजाय ध्यान भटकाने वाली कार्रवाइयों में लगी हुई है। नीट-यूजी पुनरीक्षण परीक्षा से पहले सरकार द्वारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्मों और मैसेजिंग माध्यमों पर निगरानी तथा प्रतिबंधात्मक कदम उठाए

जाने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। खरगे ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यदि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित होती और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त तैयारी की गई होती, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होतीं। उनके अनुसार देश के युवाओं को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उनकी मेहनत और योग्यता के आधार पर ही चयन होगा, न कि किसी लीक या अनियमितता के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फेरेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक के मूल नेटवर्क और कथित माफिया तक पहुंचने के बजाय छोटे स्तर पर कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की सक्रियता तभी प्रभावी मानी जाएगी जब इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद वास्तविक जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। उनके अनुसार केवल निचले स्तर के आरोपियों को गिरफ्तार कर देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। खरगे ने दावा किया कि पिछले एक दशक में देश में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े लगभग 90 पेपर लीक या परीक्षा अनियमितता के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन करोड़ों युवाओं पर पड़ा है जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा रद्द होने, पुनर्परीक्षा आयोजित होने और परिणामों पर विवाद खड़े होने से छात्रों को मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न है। पार्टी नेताओं के अनुसार यदि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं तो इससे युवाओं का संस्थागत प्रक्रियाओं पर भरोसा कमजोर होता है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार इस मामले में उच्चस्तरीय जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जांच एजेंसियां विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की जांच कर रही हैं और कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं।

नीट विवाद ने एक बार फिर देश में परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष जहां इसे सरकार की बड़ी प्रशासनिक विफलता बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

जनगणना-2027 ने पकड़ी रफ्तार, 23 राज्यों में पूरा हुआ पहला चरण, डिजिटल भारत की ओर बड़ा कदम

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाने वाली जनगणना-2027 का पहला चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना (हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस-एचएलओ) का प्रथम चरण देश के 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह प्रक्रिया न केवल देश की जनसंख्या और आवासीय स्थिति का विस्तृत आंकड़ा तैयार करने का आधार बनेगी, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और संसाधनों के वितरण की दिशा भी तय करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना-2027 का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत घरों, भवनों, परिवारों, उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। मंत्रालय का कहना है कि अब तक प्राप्त आंकड़े भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला चरण पूरा हो चुका है, उनमें Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Delhi, Goa, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Telangana और Uttarakhand शामिल हैं। इन राज्यों में घर-घर जाकर आंकड़े संग्रह करने का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 16 मई से 14 जून तक व्यापक स्तर पर मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना अभियान चलाया गया। इस दौरान लाखों घरों तक पहुंचकर आवश्यक जानकारी एकत्र की गई। इसी प्रकार पंजाब में भी यह प्रक्रिया 13 जून को सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश क्षेत्रों में लोगों ने जनगणना कर्मियों को पूरा सहयोग दिया, जिससे अभियान को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने में मदद मिली। हालांकि देश के कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया अभी जारी है। Gujarat, Jammu and Kashmir, Ladakh, Puducherry तथा Uttar Pradesh में जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में कार्य की प्रगति लगातार निगरानी में रखी जा रही है ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी की जा सके।

वहीं पर्वतीय राज्य Himachal Pradesh में मंगलवार से फील्ड ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। यहां जनगणना का कार्य 15 जुलाई तक जारी रहेगा। राज्य के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि दूरस्थ गांवों तक भी जनगणना कर्मी पहुंच सकें। इस बार जनगणना अभियान की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्व-गणना यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी है। Kerala और Nagaland में नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। यह सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इन राज्यों में भी पारंपरिक घर-घर गणना का कार्य किया जाएगा। सरकार का मानना है कि स्व-गणना व्यवस्था से नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी और आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया अधिक सुगम होगी। जनगणना-2027 कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि यह पहली ऐसी जनगणना है जिसे बड़े पैमाने पर डिजिटल माध्यमों के जरिए संचालित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं, जिनकी सहायता से गणनाकर्मी सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आंकड़े दर्ज कर रहे हैं। इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक होने की उम्मीद है।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल व्यवस्था के साथ-साथ पारंपरिक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को भी बनाए रखा गया है ताकि तकनीकी संसाधनों से दूर रहने वाले लोगों की जानकारी भी पूरी तरह दर्ज की जा सके। इस दोहरी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक जनगणना प्रक्रिया से छूट न जाए।

मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना के दौरान 33 प्रश्नों वाली अधिसूचित प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है। इसमें मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल, शौचालय, बिजली, इंटरनेट, रसोई गैस जैसी सुविधाओं की उपलब्धता, परिसंपत्तियों की स्थिति तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक विवरण शामिल हैं। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं होती, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी संरचना का विस्तृत दस्तावेज तैयार करती है।

टीएमसी बागी गुट के विलय के बाद एनसीपीआई में बड़ा बदलाव, ज्योतिप्रकाश चटर्जी बने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बनी नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की संस्थापक शिवली कुंडू के पद छोड़ने के बाद नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए ज्योतिप्रकाश चटर्जी को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं के साथ पार्टी के संबंध और राजनीतिक गतिविधियां लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।

पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की जानकारी तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट से जुड़ी प्रमुख नेता Kakoli Ghosh Dastidar ने दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनसीपीआई की कमान अब ज्योतिप्रकाश चटर्जी के हाथों में होगी और पार्टी आगे उनके नेतृत्व में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। यह बयान उस समय सामने आया जब एक दिन पहले एनसीपीआई की संस्थापक शिवली कुंडू ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ चुकी हैं।

शिवली कुंडू के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभवतः काकोली घोष दस्तीदार को सौंपी जा सकती है। टीएमसी के बागी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियों और हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसी संभावना पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि काकोली घोष दस्तीदार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि पार्टी ने ज्योतिप्रकाश चटर्जी को नया अध्यक्ष चुना है।

लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ

ही एक नया विवाद भी सामने आ गया है। राजनीतिक हलकों में सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी आखिर हैं कौन। पार्टी के भीतर भी उनके बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव दिखाई दे रहा है। दिलचस्प स्थिति यह है कि संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी नए अध्यक्ष के राजनीतिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि से परिचित नहीं हैं।

खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बताने वाले शांतनु डे ने इस मामले पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नए अध्यक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं है और पार्टी के भीतर क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, इसकी भी उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उनका कहना है कि वर्षों तक संगठन के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नेतृत्व परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखा गया है।

शांतनु डे ने कहा कि पार्टी में बड़े नेताओं का आना स्वागत योग्य है, लेकिन संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए बिना लिए जा रहे निर्णय असंतोष को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी है और कई पदाधिकारियों को अंधेरे में रखा जा रहा है। उनके बयान ने यह संकेत दिया है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद संगठन के भीतर असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल में नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब नए नेतृत्व के बारे में स्वयं संगठन के वरिष्ठ सदस्य ही अनभिज्ञ दिखाई दें तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि निर्णय प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही है। यही कारण है कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी की नियुक्ति के साथ-साथ उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

एनसीपीआई की बात करें तो यह देश की अपेक्षाकृत नई राजनीतिक पार्टियों में शामिल है। पार्टी का गठन हाल के वर्षों में हुआ और जनवरी 2023 में इसका पंजीकरण निर्वाचन आयोग में कराया गया था। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार पार्टी का आधिकारिक पता पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल क्षेत्र में दर्ज है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की पहचान अभी सीमित है, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने इसे अचानक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पार्टी ने अपने गठन के बाद पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में दी थी। उस चुनाव में एनसीपीआई ने चार उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और राजनीतिक दल-बदल के विरोध को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था। पार्टी का चुनावी नारा था—"राजनीतिक दल-बदलुओं को नकारें।" हालांकि चुनाव परिणाम पार्टी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे।

त्रिपुरा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद सीमित रहा। उसके उम्मीदवारों को बहुत कम मत प्राप्त हुए और चुनावी मुकाबले में वे प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। एक उम्मीदवार को 536 वोट मिले, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 286 मत प्राप्त हुए। पार्टी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार को 376 वोट मिले। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि उस समय पार्टी जनाधार बनाने में सफल नहीं हो सकी थी।

इसके बावजूद हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने एनसीपीआई को नई पहचान दिलाई है। विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट और बागी नेताओं के साथ उसके संबंधों ने पार्टी को राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। यही कारण है कि अब पार्टी के नेतृत्व में होने वाले बदलावों पर भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नए राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक मजबूती और स्पष्ट नेतृत्व स्थापित करना होती है। ऐसे समय में जब पार्टी अपने विस्तार और पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, नए अध्यक्ष ज्योतिप्रकाश चटर्जी के सामने संगठन को एकजुट रखने, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने और राजनीतिक दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल एनसीपीआई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति ने जितने सवालों का जवाब दिया है, उतने ही नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं और क्या वे संगठन के भीतर उभर रही असंतोष की आवाजों को शांत कर पाते हैं।

संपादकीय

फर्जी लेबल हैं जीवन से खिलवाड़

भारत में सामान्यतः उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-तिथि के दावों के बावजूद उसके सेहत से जुड़े सरोकार सवालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान की एक्सपायरी डेट दर्ज करने में हेरफेर करने तक से नहीं चूकते। यह भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उपभोक्ता अदालतों में ऐसे मामलों की गूंज रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस जारी करना, निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उजागर होते हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पार्श्व में डाल दिया जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से रेगुलेटरी संस्था को निगरानी सिर्फ कभी-कभार नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुर्खियां बनती हैं लेकिन फिर लोगों को इसकी याद कम ही रह जाती है। इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन से बचने के लिए लेबलिंग पर लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है।

निस्संदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे समय तक रहने वाली परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों पर हेल्दी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान से जुड़े दूसरे परहेजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी हानिकारक हो सकती है। उत्पादों की ईमानदारी व उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे भारतीय समाज में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान होनी चाहिए। साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की औचक निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर संस्थानों और विभिन्न मीडिया समूहों को आम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझें। कैसे भ्रमित करने वाले दावों की पड़ताल करें। साथ ही कैसे वे सेहत के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही अनैतिक मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है। खाद्य उत्पाद से जुड़े कारोबारियों को कानून के बजाय नैतिक दायित्वों के निर्वहन से कारोबार में शुचिता को बनाये रखनी चाहिए।

रिकॉर्ड के मोर्चे पर कौन भारी, कौन कमजोर

> प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्थापित हो चुका है, उसमे अगर प्रगतिशील खेमा और कांग्रेस की आलोचना के केंद्र में मोदी ना रहें तो ही हैरत होगी। प्रगतिशील खेमा मोदी को कमतर दिखाने की कोशिश में नेहरू को सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहा है।

इस बार 11 जून की तारीख भारतीय इतिहास के लिए विशेष बनकर आई। इसी दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिन शासन चलाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा 4398 दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम है। मौजूदा दौर विशेषकर विजुअल मीडिया के वर्चस्व का दौर है। विजुअल मीडिया की चूंकि उत्सवधर्मिता केंद्रित है, लिहाजा इस रिकॉर्ड को लेकर सत्ता पक्ष में उत्साह का माहौल होना ही था और ऐसा है भी। लेकिन इसे लेकर आलोचनाओं की बाढ़ भी आ गई है। विशेषकर प्रगतिशील खेमे से मोदी के इस रिकॉर्ड को लेकर तंज में आलोचनाएं की जा रही हैं। इन आलोचनाओं का भाव कुछ वैसे ही है, जैसे कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। आलोचकों की नजर में कहावत के राजा भोज नेहरू हैं और गंगू मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अरसा पहले संसद को संबोधित करते हुए देश के विकास में अतीत के हर प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया था। इतिहास क्रम में हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ योगदान दिया ही है। हर प्रधानमंत्री की युगीन आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग रही हैं।

इसलिए अव्वल तो ऐसी तुलनाएं होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि नेहरू के युग में भारत की जो स्थिति थी, वह अब नहीं है। इतिहास का कोई खंड कठिन होता है तो कोई आसान। इसलिए इतिहास के काल खंड की बुनियाद पर उस दौर के शासक की परख होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य का शासक अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता।

प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्थापित हो चुका है, उसमे अगर प्रगतिशील खेमा और कांग्रेस की आलोचना के केंद्र में मोदी ना रहें तो ही हैरत होगी। प्रगतिशील खेमा मोदी को कमतर दिखाने की कोशिश में नेहरू को सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस आलोक में इतिहास के तथ्यों को जांचना जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन वह किसी एक दल विशेष यानी कांग्रेस की ही सरकार नहीं थी, बल्कि एक तरह से वह राष्ट्रीय सरकार थी, जिसमें अंबेडकर भी थे और श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा लगने लगा था कि भारत को आजादी मिल जाएगी। इस बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने चुनावी वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भारत को स्वाधीनता दी जाएगी। जब उन्होंने ब्रिटेन की कमान संभाल ली तो उन्होंने भारत को आजादी देने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसी सिलसिले में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मिशन के सामने सवाल यह था कि सत्ता का हस्तांतरण किसे किया जाएगा, क्योंकि उन दिनों भारत में दो बड़े और प्रमुख दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन सत्ता किसे सौंपी जाए, इस सवाल के साथ ही भारत की भावी सरकार और विधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं। दूसरे दलों और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं थी। इसके पहले प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को सामान्य सीटों के नब्बे प्रतिशत हिस्से पर जीत मिली, मुस्लिम बहुल 87 प्रतिशत सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली। इसके बाद सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को ही सत्ता हस्तांतरण होना तय हुआ। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष का महत्व बढ़ गया। उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अधिकांश प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम आगे किया था, जबकि कुछ ही प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने जवाहर लाल नेहरू का नाम आगे किया। चूंकि गांधी जी पहले ही कह चुके थे कि उनके बाद जवाहर उनकी भाषा बोलेगा यानी सत्ता उन्हें मिलेगी, इसलिए वे ही अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत 2 सितंबर 1946 को 'अंतरिम सरकार' का गठन हुआ, जिसमें नेहरू जी को 'वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष' बनाया गया, उस पद का नाम प्रधानमंत्री नहीं था। इसे अंतरिम सरकार कहा गया। भले ही कुछ लोग सुविधा के लिए नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल को उसी दिन से मान लेते हैं। यहां याद करना जरूरी है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष खुद वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। उनके बाद आए वायसराय माउंटबेटन इसके अध्यक्ष रहे।

देश को स15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' के तहत देश को आजाद घोषित किया गया। इस कानून के मूल पाठ में कहीं भी "प्राइम मिनिस्टर" या प्रधानमंत्री शब्द नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पंद्रह अगस्त 1947 की आधी रात को नेहरू ने स्वाधीन सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली, भले ही वे उसके मुखिया थे। नेहरू ने अंग्रेजी में शपथ लेते हुए 'ऑफिस ऑफ मिनिस्टर' यानी मंत्री पद की शपथ ली थी, प्रधानमंत्री पद की नहीं। इसके बाद ही उन्होंने 'नियति से साक्षात्कार' वाला प्रसिद्ध भाषण दिया था। यहां याद करना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत तत्कालीन गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में दोनों उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। जिन्हें सलाह देने और शासन चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद का प्रावधान था। इस प्रावधान में प्रधानमंत्री या प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं है। गवर्नर-जनरल को इसी मंत्रि परिषद की सलाह पर शासन चलाना था। मोदी को सबसे लंबे समय तक बतौर निर्वाचित प्रधानंत्री काम करने के रिकॉर्ड को गलत साबित करने वाला प्रगतिशील तबके का तर्क है कि 1946 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन कर उभरी और उसके निर्वाचित नेता के तौर पर नेहरू ने सरकार चलाई। लेकिन हकीकत यह है कि 1946 का चुनाव वयस्क मतदान के अधिकार और एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत के तहत नहीं हुआ था। तब वोटर होने की शर्त संपत्ति, शिक्षा, कर भुगतान आदि था। मुसलमान सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों के ही मतदाता थे। एक तरह से यह सार्वभौम वयस्क मतदान के अधिकार से रहित चुनाव था। इसलिए सही मायने में 1946 का चुनाव ना तो समानता और वयस्क मतदान के अधिकार से लैस था, न ही पूरे देश के मतदाताओं का प्रतिबिंब था। एक तरह से कहें तो यह सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के मतदान की बुनियाद पर हुआ चुनाव था। जिसमें हर वयस्क की भागीदारी नहीं थी। उन दिनों धार्मिक आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र भी थे। इसलिए 1946 का चुनाव सही मायने में संतुलित मतदान नहीं था। स्वाधीन भारत में पहला आम चुनाव 1951 -52 के बीच हुआ। जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिलीं। इसी नतीजे के आधार पर पंडित नेहरू ने 13 मई 1952 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 27 मई 1964 को मृत्यु पर्यंत अपने पद पर रहे। इसी लिहाज से नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन ही होता। आधुनिक सार्वभौम मतदान के अधिकार और सिद्धांत के लिहाज से देखें तो पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर असल कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक का ही होता है।

रही बात नेहरू और मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की, तो इसकी तुलना की जा सकती है। भारत की आजादी के वक्त देश में बीस विश्वविद्यालय थे, जिसे नेहरू ने अपने कार्यकाल में 64 तक पहुंचा दिया था। इस लिहाज से देखें तो मोदी के कार्यकाल में देश में साढ़े पांच सौ से ज्यादा विश्वविद्यालय हो चुके हैं। नेहरू समर्थक कह रहे हैं कि आजादी के वक्त देश में 15 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर नेहरू ने 81 कर दी थी। लेकिन जब मोदी ने कार्यकाल संभाला तो देश में 393 मेडिकल कॉलेज थे, जिसे उन्होंने 818 तक कर दिया है। 431 मेडिकल कॉलेज तो 2014 के बाद ही बने हैं। बेशक नेहरू अपनी विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोदी ने भारत के स्वत्व बोध को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब बढ़ाया है।

प्रेरणा

तपोवन : जहां कालनेमि के अंत और हनुमान की विजय की अमर गाथा आज भी जीवित है

हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां का प्रत्येक पर्वत, नदी, घाटी और वन किसी न किसी दिव्य कथा का साक्षी रहा है। इसी देवभूमि के चमोली जनपद की नीति घाटी में स्थित तपोवन एक ऐसा पावन स्थल है, जिसका संबंध सीधे रामायणकाल की उन घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, जिन्होंने धर्म और अधर्म के महायुद्ध की दिशा बदल दी थी। स्थानीय मान्यताओं, लोककथाओं तथा प्राचीन साहित्य में वर्णित कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां संजीवनी बूटी की खोज में निकले पवनपुत्र हनुमान का सामना मायावी राक्षस कालनेमि से हुआ था और जहां अधर्म पर धर्म की एक और निर्णायक विजय हुई थी।

त्रेतायुग में जब भगवान श्रीराम और रावण के बीच लंका में भीषण युद्ध चल रहा था, तब युद्ध के मैदान में रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्रीराम अपने प्रिय अनुज की अवस्था देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। समूची वानर सेना शोक में डूब गई। उस समय लंका में उपस्थित महान वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी और स्थिति का परीक्षण किया तथा गंभीर स्वर में बताया कि यदि अर्द्धरात्रि से पूर्व हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर उन्हें दी जाए, तभी उनके प्राण बच सकते हैं। समय अत्यंत कम था और कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। तब सुषेण वैद्य ने कहा कि इस दुष्कर कार्य को केवल पवनपुत्र हनुमान ही पूरा कर सकते हैं। श्रीराम ने हनुमान की ओर देखा और आदेश दिया कि वे तत्काल हिमालय जाकर संजीवनी बूटी लेकर आएं। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान बिना विलंब आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। उनका वेग मन और वायु के समान था। इसी कारण उन्हें "मनोजवं मारुततुल्यवेगम्" कहा जाता है।

उधर लंका में बैठे रावण को जब यह समाचार मिला कि हनुमान संजीवनी बूटी लाने निकल चुके हैं, तो वह चिंतित हो उठा। वह भलीभांति जानता था कि यदि लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए तो राम की सेना का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा और उसकी पराजय निश्चित हो जाएगी। उसने अपने विश्वासपात्र राक्षस कालनेमि को बुलाया और आदेश दिया कि किसी भी प्रकार हनुमान के मार्ग में बाधा उत्पन्न की जाए। कालनेमि ने पहले तो रावण को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि जिसने अकेले लंका में प्रवेश कर नगर को जला दिया, अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया और असंख्य राक्षसों का संहार कर दिया, उसके मार्ग को रोकना किसी साधारण कार्य की बात नहीं है। किंतु रावण के क्रोध और अहंकार के सामने उसकी एक न चली।

अंततः कालनेमि ने मन ही मन विचार किया कि यदि मृत्यु निश्चित है तो रावण के हाथों अपमानजनक मृत्यु पाने से कहीं श्रेष्ठ है कि श्रीराम के परम भक्त हनुमान के हाथों उसका अंत हो। ऐसा सोचकर वह हिमालय की ओर चल पड़ा और तपोवन क्षेत्र के निकट अपनी मायावी शक्तियों से एक सुंदर आश्रम, भव्य मंदिर, रमणीय उपवन और शांत जलाशय की रचना कर दी। उसका उद्देश्य हनुमान को कुछ समय के लिए भ्रमित कर उनकी यात्रा में विलंब उत्पन्न करना था।

जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तब उनकी दृष्टि उस आश्रम पर पड़ी। वहां एक तपस्वी के वेश में कालनेमि बैठा हुआ था। उसने अत्यंत विनम्रता और मधुरता के साथ हनुमान का स्वागत किया। हनुमान ने भी उसे एक साधु समझकर प्रणाम किया। कालनेमि ने अपनी माया का जाल फैलाना शुरू किया। वह श्रीराम के गुणों का बखान करने लगा और बोला कि राम और रावण के युद्ध में अंततः राम की ही विजय होगी। उसने यह भी कहा कि वह यहां तपस्या करता है और अपनी ज्ञानदृष्टि से सब कुछ देख सकता है।

हनुमान को उस समय अत्यधिक प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस मुनि से जल मांगा। कालनेमि ने उन्हें अपने कमंडल का जल दिया, किंतु हनुमान की प्यास उससे नहीं बुझी। तब उसने पास स्थित जलाशय की ओर संकेत करते हुए कहा कि वहां स्नान और जलपान करके लौट आएं, फिर वह उन्हें एक दिव्य मंत्र की दीक्षा देगा जिससे उनका कार्य और भी सरल हो जाएगा। हनुमान उस जलाशय में उतरे ही थे कि अचानक एक विशाल मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। पवनपुत्र ने तत्काल उसे पकड़कर बाहर खींच लिया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। किंतु जैसे ही वह मगरी मरी, उसी क्षण वह एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। उसने हनुमान को प्रणाम किया और कहा कि वह एक शाप के कारण मगरी योनि में पड़ी हुई थी। आज उनके दर्शन और स्पर्श से उसका उद्धार हो गया है। उसने हनुमान को सावधान करते हुए बताया कि जिसे वे साधु समझ रहे हैं, वह वास्तव में कालनेमि नामक भयंकर राक्षस है, जो उन्हें धोखा देकर उनके कार्य में बाधा डालना चाहता है।

अप्सरा के स्वर्गलोक को प्रस्थान करते ही हनुमान सब समझ गए। वे तुरंत आश्रम में लौटे और कालनेमि के सामने जाकर मुस्कराते हुए बोले, "हे मुनिवर, दीक्षा देने से पहले गुरुदक्षिणा स्वीकार कर लीजिए।" कालनेमि कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हनुमान ने अपनी विशाल पूंछ से उसे जकड़ लिया। फिर उसे आकाश में घुमाकर भूमि पर पटक दिया। उस प्रचंड प्रहार से उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और उसका वास्तविक राक्षसी स्वरूप प्रकट हो गया।

मृत्यु के अंतिम क्षणों में कालनेमि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान राम का स्मरण किया और "राम-राम" कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार तपोवन की पवित्र भूमि पर अधर्म का अंत हुआ और हनुमान अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ गए। बाद में जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो अनेक दिव्य औषधियों के बीच संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके। समय तेजी से बीत रहा था। तब उन्होंने संपूर्ण पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। उसी संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हुए और धर्म की सेना को नई शक्ति मिली। आज भी चमोली जिले की नीति घाटी में स्थित तपोवन को इस अद्भुत घटना का साक्षी माना जाता है। द्रोणागिरी पर्वत, संजीवनी शिखर और तपोवन का क्षेत्र श्रद्धालुओं तथा शोधकर्ताओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां की लोक परंपराओं में हनुमान और कालनेमि की कथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि सत्य, निष्ठा, भक्ति और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का संदेश भी देती है। तपोवन की शांत वादियों में आज भी मानो पवनपुत्र हनुमान के अदम्य साहस, अपार शक्ति और श्रीराम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की गूंज सुनाई देती है, जो युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा देती रहेगी।

Ethanol Fuel आपकी गाड़ी की उम्र घटाएगा या पैसा बचाएगा? E-100 पर आखिर इतना बड़ा दाँव क्यों लगा रही है मोदी सरकार?

भारत अब पेट्रोल और डीजल पर निर्भर अर्थव्यवस्था से निकलकर वैकल्पिक ईंधन की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E-100 ईंधन के मानकों को मंजूरी देकर देश की ऊर्जा नीति में एक नई बहस और नई उम्मीद दोनों को जन्म दिया है। इस फैसले के बाद इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था को लेकर सरकार, वाहन कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यही ईंधन भारत को कच्चे तेल के वैश्विक झटकों से बचाने का मजबूत आधार बन सकता है। हम आपको बता दें कि E-100 ऐसा ईंधन है जिसमें लगभग सौ प्रतिशत इथेनॉल होता है और पारंपरिक पेट्रोल की मिलावट नहीं के बराबर रहती है। इथेनॉल गन्ना, मक्का, खराब अनाज और कृषि अपशिष्ट जैसे स्रोतों से तैयार किया जाता है। अभी देश में E-20 मिश्रण वाला पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है जिसमें बीस प्रतिशत इथेनॉल और अस्सी प्रतिशत पेट्रोल होता है। लेकिन E-100 पूरी तरह इथेनॉल आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत है। मोदी सरकार की नजर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सुरक्षा पर भी है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चे तेल के रूप में खरीदता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ते ही देश का आयात बिल और महंगाई दोनों बढ़ जाती हैं। ऐसे में सरकार इथेनॉल आधारित ईंधन को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का रास्ता मान रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के कारण अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कच्चे तेल आयात की बचत हुई है, जबकि किसानों को लगभग अस्सी हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय मिली है। ऊर्जा विशेषज्ञ भी इसे भारत की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा मान रहे हैं। केपीएमजी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इथेनॉल आधारित बदलाव भारत के परिवहन ऊर्जा ढांचे को मजबूत बना सकता है और वैश्विक तेल संकटों से देश को बचाने में मददगार साबित हो सकता है। देखा जाये तो E-100 ईंधन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इससे किसानों की भूमिका सीधे ऊर्जा अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगी। गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। लंबे समय से खेती में लागत और लाभ के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए यह अतिरिक्त आय का नया रास्ता बन सकता है। सरकार इसी वजह से इसे कृषि और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों के लिए दोहरा लाभ मान रही है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या E-100 पेट्रोल की पूरी तरह जगह ले सकता है। जवाब है, हां लेकिन तुरंत नहीं। देश की करोड़ों गाड़ियां अभी पारंपरिक पेट्रोल या E-20 ईंधन के हिसाब से बनी हैं। उन्हें सीधे E-100 पर चलाना संभव नहीं है। इथेनॉल का व्यवहार पेट्रोल से अलग होता है। इससे इंजन की संरचना, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और पाइप लाइन तक में बदलाव करना पड़ता है। यही वजह है कि अब वाहन कंपनियां विशेष फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाले वाहन विकसित कर रही हैं। मारुति सुजूकी ने वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पेश कर संकेत दे दिया है कि कम कीमत वाली जनसाधारण की गाड़ियां भी इथेनॉल आधारित तकनीक पर लाई जा सकती हैं। इसके अलावा टोयोटा, एमजी, हुंडई और सुजुकी भी ऐसे उत्पादों पर काम कर रही हैं। दोपहिया क्षेत्र में हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर और एच एफ डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल संस्करण सामने रखे हैं। इससे साफ है कि उद्योग जगत अब इस बदलाव को गंभीरता से लेने लगा है। देखा जाये तो E-100 के कई फायदे हैं। सबसे पहला लाभ विदेशी तेल पर निर्भरता कम होना है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरा बड़ा लाभ पर्यावरण को होगा क्योंकि इथेनॉल पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ माना जाता है और इससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। तीसरा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा जहां इथेनॉल उत्पादन से कृषि आधारित उद्योगों को नई गति मिल सकती है। वैसे इथेनॉल को लेकर आम उपभोक्ताओं के मन में अभी भी कई तरह की आशंकाएं हैं। सबसे बड़ी चिंता गाड़ी के इंजन और उसकी उम्र को लेकर है। बहुत से वाहन मालिक मानते हैं कि अधिक इथेनॉल मिश्रण से इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, माइलेज घट सकता है और लंबे समय में फ्यूल पाइप, रबर पाट्र्स तथा इंजेक्टर जैसे हिस्सों को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पेट्रोल वाहन पूरी तरह इथेनॉल आधारित ईंधन के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि लोग अपने मौजूदा वाहन में अधिक इथेनॉल वाला ईंधन डलवाने से हिचक रहे हैं। हालांकि नई फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली गाड़ियां विशेष रूप से इथेनाल के हिसाब से तैयार की जा रही हैं, इसलिए उनमें ऐसी आशंकाएं कम होंगी। सरकार और कंपनियां यह दावा कर रही हैं कि सही तकनीक वाले इंजनों में इथेनॉल से गाड़ी की आयु पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं का भरोसा जीतना अभी बाकी है।

कीमत को लेकर भी बहस तेज है। माना जा रहा है कि देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इथेनॉल आधारित ईंधन पेट्रोल की तुलना में सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि इसका स्रोत घरेलू कृषि क्षेत्र है और इसमें आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम रहती है। फिर भी आम लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब मौजूदा E-20 ईंधन में बीस प्रतिशत इथेनॉल मिला हुआ है, तब उपभोक्ताओं से पूरी तरह पेट्रोल जैसी कीमत क्यों वसूली जा रही है। आलोचकों का तर्क है कि यदि पेट्रोल की मात्रा कम है तो कीमत में भी उसका असर दिखना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ईंधन मूल्य निर्धारण केवल कच्चे तेल की मात्रा से तय नहीं होता, बल्कि उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और कर व्यवस्था जैसे कई पहलू उसमें शामिल रहते हैं। साथ ही डीजल में इथेनॉल मिलाने को लेकर अभी व्यापक स्तर पर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है, क्योंकि डीजल इंजन की तकनीक पेट्रोल इंजनों से अलग होती है और उसमें इथेनॉल मिश्रण को लेकर ज्यादा तकनीकी चुनौतियां हैं।

अभियान

जहां बाबा की मुस्कान में दिखते हैं हनुमान, कैंची धाम में आज भी जागृत है कृपा, करुणा और चमत्कार का दिव्य लोक

उत्तराखंड की पावन धरती पर स्थित कुछ तीर्थ ऐसे हैं, जहां पहुंचते ही मनुष्य स्वयं को किसी दूसरी ही दुनिया में अनुभव करने लगता है। वहां न केवल प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है। नैनीताल जनपद की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच स्थित कैंची धाम ऐसा ही एक दिव्य तीर्थ है, जहां लाखों श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति, विश्वास और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि यह केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आज भी बाबा नीम करौली महाराज की कृपा और पवनपुत्र हनुमान का आशीर्वाद निरंतर बरस रहा है।

कहा जाता है कि ईश्वर जब किसी संत को धरती पर भेजते हैं तो उसका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं होता, बल्कि लोगों के जीवन में प्रकाश भरना होता है। बाबा नीम करौली महाराज भी ऐसे ही संतों में गिने जाते हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण सेवा, प्रेम, करुणा और भक्ति के लिए समर्पित था। उन्होंने कभी स्वयं को चमत्कारी संत नहीं कहा, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले असंख्य लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए, जिन्हें वे ईश्वरीय कृपा से कम नहीं मानते। हिमालय की तलहटी में बसा कैंची धाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जितना आकर्षक है, उससे कहीं अधिक अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण प्रसिद्ध है। जब कोई श्रद्धालु यहां पहुंचता है तो सबसे पहले उसे वातावरण में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। पर्वतों से उतरती शीतल हवाएं, वृक्षों की हरियाली, मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि और रामनाम का सतत स्मरण मन को भीतर तक स्पर्श कर जाता है। ऐसा लगता है मानो यह स्थान संसार की भागदौड़ से दूर किसी दिव्य लोक का द्वार हो।

कैंची धाम का इतिहास केवल एक आश्रम की स्थापना का इतिहास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना का इतिहास है जिसने देश और दुनिया के लाखों लोगों को प्रभावित किया। बाबा नीम करौली महाराज ने यहां जो दीपक जलाया था, उसकी रोशनी आज भी अनगिनत जीवनों को दिशा दे रही है। वर्ष 1964 में स्थापित यह आश्रम धीरे-धीरे भक्ति और सेवा का ऐसा केंद्र बन गया, जिसकी ख्याति सात समंदर पार तक पहुंच गई। बाबा का जीवन अत्यंत सरल था। वे वैभव, प्रसिद्धि और दिखावे से दूर रहते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा था। वे कहा करते थे कि भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची पूजा है। उनके जीवन का यही संदेश आज भी कैंची धाम की आत्मा बनकर जीवित है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल पूजा-अर्चना ही नहीं करता, बल्कि सेवा और प्रेम की भावना को भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर लौटता है। बाबा नीम करौली महाराज का हृदय भगवान हनुमान की भक्ति में पूरी तरह समर्पित था। वे हनुमान जी को केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर प्रेम का सजीव स्वरूप मानते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति हनुमान जी की तरह अहंकार त्यागकर प्रभु की सेवा करता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है कि कैंची धाम में हनुमान मंदिर सबसे प्रमुख स्थान रखता है।

मंदिर में स्थापित हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन करते ही श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। अनेक भक्त बताते हैं कि यहां आकर उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं बजरंगबली उनकी पुकार सुन रहे हों। संकटों से घिरे लोग यहां आकर राहत महसूस करते हैं और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों को नई आशा मिलती है। कैंची धाम का सबसे बड़ा आकर्षण केवल मंदिर या भवन नहीं हैं, बल्कि वह अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे यहां आने वाले लोग महसूस करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे बाबा की समाधि के सामने बैठते हैं तो उनकी आंखें स्वतः नम हो जाती हैं। मन में चल रहा तनाव समाप्त होने लगता है और भीतर से एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। ऐसा लगता है मानो बाबा स्वयं अपने भक्तों के मन की बात सुन रहे हों।

बाबा की समाधि आज भी करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। यहां लोग अपनी परेशानियां, इच्छाएं और जीवन की उलझनें बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते हैं। यही कारण है कि वर्षभर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।

कैंची धाम में केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अनेक विदेशी साधक यहां ध्यान और आध्यात्मिक शांति की खोज में आते हैं। बाबा की शिक्षाओं ने दुनिया के विभिन्न देशों में लोगों को प्रभावित किया है। प्रेम, सेवा और ईश्वर स्मरण का उनका संदेश किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं था। उन्होंने मानवता को ही अपना धर्म माना। बाबा कहा करते थे कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। यदि मनुष्य अपने भीतर प्रेम विकसित कर ले, तो उसके जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि कैंची धाम में किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता। यहां हर व्यक्ति समान है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, भारतीय हो या विदेशी—सभी बाबा के दरबार में समान भाव से बैठते हैं। आश्रम परिसर में स्थित मंदिरों में दिनभर भक्ति का वातावरण बना रहता है। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होता है, कहीं रामनाम का संकीर्तन, तो कहीं श्रद्धालु ध्यान में लीन दिखाई देते हैं। यहां की प्रत्येक ध्वनि और प्रत्येक गतिविधि मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का कार्य करती है। हर वर्ष 15 जून को कैंची धाम में प्रतिष्ठा दिवस का विशाल आयोजन होता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का महासंगम होता है। लाखों भक्त दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं। पूरी रात भजन-कीर्तन चलता है। विशाल भंडारों का आयोजन होता है और हजारों स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुट जाते हैं। उस दिन ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण हनुमान भक्ति और बाबा की कृपा से आलोकित हो उठा हो।

कहा जाता है कि बाबा को कंबल अत्यंत प्रिय था। वे प्रायः एक साधारण कंबल ओढ़कर ही रहते थे। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु बाबा को कंबल अर्पित करते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि जैसे बाबा ने अपने जीवन में लोगों को सुरक्षा और स्नेह प्रदान किया, वैसे ही उनका आशीर्वाद आज भी भक्तों को जीवन की कठिन परिस्थितियों से बचाता है। कैंची धाम की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती। यहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं के भीतर झांकना सीखता है। उसे यह समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक सुख धन, पद और प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और ईश्वर के स्मरण में छिपा है। यही कारण है कि यहां आने वाले अनेक लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों का स्पर्श करती हैं और मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, तब कैंची धाम का वातावरण किसी स्वर्गिक लोक जैसा प्रतीत होता है। श्रद्धालु रामनाम का जाप करते हुए मंदिरों की ओर बढ़ते हैं और उनके चेहरों पर एक अनोखी शांति दिखाई देती है। यह वही शांति है जिसकी तलाश में आधुनिक मनुष्य दुनिया भर में भटकता है।

आज भी लाखों लोगों का विश्वास है कि बाबा नीम करौली महाराज कहीं नहीं गए हैं। वे अपने भक्तों के बीच उसी प्रकार उपस्थित हैं जैसे पहले थे। उनकी करुणा, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद आज भी कैंची धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि यहां से लौटने वाला व्यक्ति केवल प्रसाद लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने साथ विश्वास, आशा और भक्ति की ऐसी अमूल्य पूंजी लेकर लौटता है जो उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। कैंची धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। यह वह भूमि है जहां भक्ति और सेवा एक साथ चलती हैं, जहां हनुमान जी की शक्ति और बाबा की करुणा एक साथ अनुभव होती है, और जहां पहुंचकर मनुष्य यह महसूस करता है कि ईश्वर आज भी अपने भक्तों के बहुत निकट हैं। यही कारण है कि हिमालय की गोद में बसा यह पावन धाम करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवित आस्था, जागृत कृपा और अनंत प्रेम का दिव्य मंदिर बन चुका है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

‘सुरक्षित प्रवासन एवं बाल मजदूरी उन्मूलन’ एक मानवीय कर्तव्य है; जिसे हम सभी मिलकर निभाएं : श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया

▸▸ हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का समान अधिकार : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती धर्मिष्ठाबेन गज्जर

▸▸ ’विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ के अवसर पर स्पीपा, गांधीनगर में दो दिवसीय अंतर्राज्यीय चर्चा का शुभारंभ हुआ

गांधीनगर : श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया ने स्पीपा, गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर कहा कि श्रम नीति केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित न रहकर प्रत्येक श्रमिक परिवार और उसके बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। ‘सुरक्षित प्रवासन और बाल मजदूरी उन्मूलन’ एक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय कर्तव्य है, जिसे हम सभी को मिलकर निभाना है।

12 जून – विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के संदर्भ में बाल मजदूरी रोकथाम, बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों के सर्वांगीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित दो दिवसीय अंतर्राज्यीय चर्चा का आयोजन मंगलवार को स्पीपा, गांधीनगर में श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया की विशेष उपस्थिति में किया गया।

भारत की निरंतर विकास यात्रा में प्रवासी श्रमिकों के असाधारण योगदान की सराहना करते हुए मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया ने कहा कि देश के उद्योगों, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का विकास प्रवासी श्रमिकों की मेहनत पर आधारित है, जो राष्ट्र निर्माण के वास्तविक आधारस्तंभ हैं। गुजरात जैसे प्रगतिशील और औद्योगिक राज्य में भी विभिन्न राज्यों से लाखों श्रमिक रोजगार के लिए आते हैं और राज्य की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनते हैं।

मंत्री श्री बावळिया ने जोड़ा कि इस प्रवासन के साथ अनेक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जब कोई श्रमिक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तब उनके बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और कई बार वे सामाजिक सुरक्षा तथा बाल संरक्षण से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां बाल मजदूरी, बाल तस्करी और शोषण जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती हैं। इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक बहुआयामी एवं सक्रिय प्रयास कर रही हैं। राज्य में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए जिला स्तर पर कार्यरत टास्क फोर्स को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर बच्चों के बचाव, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाया गया है। श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण, व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इस अवसर पर मंत्री ने दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बाल मजदूरी का उन्मूलन केवल कानूनों के क्रियान्वयन से संभव नहीं होगा। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। श्री बावळिया ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि “आइए, हम सभी मिलकर संकल्प लें कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक परिवार को अधिक सम्मानजनक जीवन मिले और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य का अधिकार प्राप्त हो।”

इस अवसर पर गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती धर्मिष्ठाबेन गज्जर ने कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों, सपनों और उनके भविष्य पर सीधा प्रहार है। देश के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का समान अधिकार है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए आज के बच्चों का शिक्षित और सुरक्षित होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करना होगा। देश का कोई भी बच्चा मजबूरी में श्रम करने के लिए विवश न हो, इस उद्देश्य से सरकार, सामाजिक नेताओं और स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलकर कार्य करना होगा।

बाल श्रम और मानव तस्करी के जोखिमों को रोकने के लिए उन्होंने सभी राज्यों से समन्वित और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान, बच्चों की ट्रैकिंग व्यवस्था और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बना सकें, तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गुजरात सरकार ने इस दिशा में ‘राज्य कार्य योजना’ तैयार करके एक सराहनीय कदम उठाया है।

श्रम आयुक्त श्री के.डी. लाखाणी ने कहा कि बाल मजदूरी केवल कानूनी या आर्थिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा व्यापक सामाजिक मुद्दा है। देश के विभिन्न राज्यों से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा, पोषण और सुरक्षा की सुविधाएं लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं और नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय नहीं देखना चाहता, इसलिए बाल मजदूरी के पीछे मौजूद मूल कारणों को समझना और उनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।

श्री लाखाणी ने आगे कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रवासन और बाल मजदूरी के जोखिमों, बाल मजदूरी रोकथाम के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, बचाव, पुनर्वास और पुनःसमावेशन की प्रक्रियाओं तथा समुदाय आधारित हस्तक्षेपों जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभिन्न राज्यों के अनुभवों, सफल मॉडलों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से बाल मजदूरी मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रभावी रोडमैप तैयार करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है।

इस अवसर पर एमजीएलआई के महानिदेशक श्री प्रवीण सोलंकी ने कहा कि बाल मजदूरी कोई अलग समस्या नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। विशेष रूप से जब हमारा देश तीव्र विकास के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब बाल मजदूरी समाज के लिए एक कलंक है, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। देशभर में कानून और नियम समान होने के बावजूद विभिन्न राज्यों के परिणाम अलग-अलग होते हैं, इसलिए इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी प्रतिभागी खुले मन से अपने अच्छे और बुरे अनुभव साझा करें।

कार्यक्रम में यूनिसेफ के सीएफओ डॉ. नारायण गावकर ने कहा कि गुजरात एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने के कारण यहां अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक प्रवास करते हैं। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की कीमत पर न हो। प्रवासन भले ही रोजगार के अवसर प्रदान करता हो, लेकिन बच्चे जहां भी जाएं, उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि यूनिसेफ वर्षों से सरकार और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर बाल मजदूरी रोकने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए यूनिसेफ द्वारा तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। पहला; परिवारों को अधिक सशक्त बनाना ताकि बच्चों को प्रवास न करना पड़े और बाल मजदूरी की रोकथाम हो सके। दूसरा; किशोरों को उचित शिक्षा, कौशल और सुरक्षित रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देना। तीसरा; शिक्षा को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानते हुए बच्चों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराना।

सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (स्पीपा) में श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग, महात्मा गांधी लेबर संस्थान (एमजीएलआई) और यूनिसेफ गुजरात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चर्चा सत्र के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, बाल अधिकार क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं तथा विषय विशेषज्ञ बाल मजदूरी उन्मूलन के सर्वोत्तम प्रयासों, सफल मॉडलों और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान-प्रदान से बाल मजदूरी मुक्त समाज और देश के निर्माण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

इस अवसर पर गुजरात सहित राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आई डिजिटल क्रांति

आज गुजरात में 6.99 करोड़ बचत खातों में कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग की सुविधा

▸▸ गुजरात प्रत्येक नागरिक को ह्यूमन कैपिटल के रूप में विकसित और सशक्त करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन : 10 वर्षों में 12 हजार गुना वृद्धि हुई, 2025-26 में हुआ 314 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन

▸▸ यूपीआई पेमेंट, डीबीटी और सरकारी सेवाएं डिजिटल होने से नागरिकों की सुविधा में हुई वृद्धि

गांधीनगर : श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई, 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके 12 वर्षों के कार्यकाल में भारत विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए अध्याय लिखे हैं। विशेषकर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, उत्पादन, खेल और सामाजिक सुधार जैसे अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति उल्लेखनीय रही है। भारत आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। गत 12 वर्षों में विभिन्न डिजिटल पहलों से नागरिकों की सुख-सुविधा में बढ़ोतरी देखी गई है।

गुजरात में 6.99 करोड़ बचत खातों में डिजिटल बैंकिंग की सुविधा

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में 31 मार्च, 2026 तक 6,99,05,125 बचत खातों में कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बैंकिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ाने को कहा गया है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से तेजी और आसानी से बैंकिंग लेनदेन कर सकें।

आज 6.99 करोड़ बचत खातों में से 70.49 फीसदी खाताधारकों के पास डेबिट कार्ड है, जबकि 63.19 फीसदी खाताधारक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), मोबाइल बैंकिंग और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा-यूएसएसडी (बिना इंटरनेट वाले फोन से बैंकिंग) सेवाओं का उपयोग करते हैं। वहीं, 79.20 फीसदी धारक आधार कार्ड की मदद से बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करते हैं। गुजरात में आज 1,98,52,734 जनधन लाभार्थी हैं और 1,51,79,955 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई डिजिटल क्रांति के कारण आज कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं तेजी से पहुंची हैं।

10 वर्षों में यूपीआई लेनदेन की मात्रा में 12 हजार गुना वृद्धि, 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 11 अप्रैल, 2016 को लॉन्च किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर लेनदेन की मात्रा 2016-17 में 2 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ पर पहुंच गई है, जो 12 हजार गुना वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार, वर्ष 2016 में यूपीआई के माध्यम से हुए लेनदेन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो दस वर्षों में लेनदेन के मूल्य में 4000 गुना वृद्धि दिखाता है।

आज भारत में दैनिक औसतन 66 करोड़ यूपीआई लेनदेन होते हैं, जिनका औसत दैनिक मूल्य 0.86 लाख करोड़ रुपए है। यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों से बढ़कर मार्च 2026 तक 703 हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार भारत के डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का योगदान 85 फीसदी है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस और कतर में भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत 12 वर्षों में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई है। अभी भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है, जो 12 वर्ष पहले 25 करोड़ थी। इंटरनेट उपभोक्ताओं में वृद्धि और संसद से लेकर पंचायतों तक को ‘भारतनेट’ से जोड़ना डिजिटल इंडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतनेट परियोजना के तहत 12 वर्ष पहले केवल 546 पंचायतें जुड़ी थीं, लेकिन आज 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इस परियोजना के साथ जुड़ चुकी हैं।

अब गुजरात तथा भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एक क्लिक में उपलब्ध है। इससे नागरिकों तक तेज, सुगम और पारदर्शी तरीके से सेवाओं का वितरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित हुआ है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं डीआरएम अहमदाबाद ने गुजरात के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ की बैठक

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय एवं अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल तथा राज्य के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास के साथ आज दिनांक 16.06.2026 को शिष्टाचार भेंट एवं समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान राज्य में रेल अवसंरचना विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार, विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की प्रगति तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने रेलवे परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं जनहित से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए बेहतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान अहमदाबाद, साबरमती सहित अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति एवं विभिन्न समन्वय संबंधी विषयों पर चर्चा की।

महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने पश्चिम रेलवे द्वारा गुजरात में संचालित प्रमुख विकास कार्यों की जानकारी साझा की, डीआरएम श्री वेद प्रकाश ने अहमदाबाद मंडल में चल रही परियोजनाओं एवं यात्री सुविधाओं के उन्नयन से संबंधित पहलुओं से अवगत कराया।

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और राज्य में सुरक्षित, आधुनिक एवं विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के विकास हेतु पारस्परिक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

बिजली के खंभों के मुआवजे के मुद्दे पर किसानों का गुस्साः गांधीनगर में ट्रैक्टर रैली के साथ मार्च निकाला गया, अहमदाबाद में पुलिस ने रोका

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात के कई इलाकों से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और गांधीनगर की ओर मार्च किया, जिसके बाद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिसमें महिला किसान भी शामिल थीं।

गुजरात के कई जिलों में किसान अपने खेतों में बिजली के खंभे लगाने और इसके लिए पर्याप्त मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। गुजरात के कई स्थानों से किसानों ने इस मुद्दे और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों के विरोध में कल ट्रैक्टर रैलियां निकालीं और गांधीनगर की ओर मार्च किया।

रैली की अनुमति न मिलने पर भारी पुलिस बल ने अहमदाबाद रिंग रोड पर किसानों की रैली को रोक दिया। इसके चलते कुछ समय तक पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। रैली रोके जाने के कारण किसान गांधीनगर जाकर अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके। इस रैली की खास बात यह थी कि महिला किसान भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुईं और किसानों के लिए न्याय की मांग की।

किसान संघर्ष समिति और किसान कांग्रेस समेत विभिन्न किसान संगठनों ने किसानों की ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इसमें किसानों के अलावा गुजरात कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। इस रैली में सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठा हुए और अपनी समस्याओं को उठाया।

वाहन पर पेड़ गिरने को ‘मोटर दुर्घटना’ नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पीड़ित को 25 लाख रुपये का मुआवजा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि मानसून के दौरान किसी वाहन पर पेड़ गिरने की घटना को “मोटर वाहन का उपयोग” अधिनियम के अंतर्गत दुर्घटना नहीं माना जा सकता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी घटना के पीड़ित को 17.10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का आदेश दिया।

2007 में घटी एक घटना में, के. के. उमेशकुमार बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम से क्वींस रोड की ओर ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, तभी एक पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर गया। इस घटना में वे घायल हो गए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस घटना के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और बीमा कंपनी तथा कर्नाटक सरकार के संबंधित विभाग को मुआवजा देने का आदेश दिया।

इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों संस्थानों को दोषी नहीं ठहराया और इस घटना को “दैवीय घटना” यानी प्राकृतिक आपदा करार दिया। हालांकि, घटना की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने पीड़ित को अधिक मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

दिल्ली में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क पर बड़ी चोट, सात गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश विफल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े आतंकी खतरे को समय रहते नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी-अपराध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई को हाल के वर्षों में आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़ के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क न केवल अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था, बल्कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी भी कर रहा था। स्पेशल सेल की कार्रवाई में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर पाकिस्तान में बैठे आतंक समर्थक तत्वों और अपराध जगत से जुड़े संचालकों के निर्देश पर काम करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस कार्रवाई से एक ऐसी साजिश को विफल किया गया है, जो सफल हो जाती तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह नेटवर्क गैंगस्टर से आतंकवादी बने शाहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर से जुड़ा हुआ था। दोनों लंबे समय से सीमा पार बैठे अपराध और आतंक के गठजोड़ को संचालित कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में अवैध हथियार पहुंचाने, युवाओं की भर्ती करने, आपराधिक गिरोहों को मजबूत बनाने और अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूर्वी रेंज को इस नेटवर्क की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके बाद कई सप्ताह तक तकनीकी निगरानी, मानव स्रोतों और गुप्त सूचनाओं के आधार पर अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्धों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस पूरे अभियान का नेतृत्व इंस्पेक्टर राहुल कुमार, विनीत कुमार तेवतिया और अजीत कुमार ने किया, जबकि इसकी निगरानी एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट द्वारा की गई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई अत्यंत गोपनीय तरीके से संचालित की गई ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्य सतर्क न हो सकें और पूरे मॉड्यूल को एक साथ पकड़ने में सफलता मिल सके। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनस, मोहित, दीपक, आरिफ, करणवीर सिंह, जतन और साबिर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये सभी अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य कर रहे थे। कुछ आरोपी हथियारों की सप्लाई और परिवहन में शामिल थे, जबकि अन्य नेटवर्क के लिए स्थानीय स्तर पर संपर्क और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, सात मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद हथियारों की गुणवत्ता और क्षमता इस बात की ओर संकेत करती है कि इनका उपयोग किसी बड़ी आपराधिक या आतंकी कार्रवाई में किया जा सकता था। जांच में सबसे महत्वपूर्ण सुराग मोबाइल फोन से मिले हैं। पुलिस के अनुसार मोबाइल उपकरणों में कई आपत्तिजनक चैट, वॉयस नोट और डिजिटल संचार सामग्री मिली है, जिनका संबंध कथित रूप से शाहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर से जुड़ा हुआ है।

आकाशीय आपदाओं के खिलाफ गुजरात सरकार का सुरक्षा कवच

▸▸ पिछले 10 वर्षों में 1.36 करोड़ किसानों को 22,733 करोड़ रुपए की राहत सहायता

▸▸ केवल एक वर्ष में 36.74 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 10,337 करोड़ रुपए

▸▸ एसडीरएफ के अलावा राज्य सरकार ने अपने स्वयं के कोष से 6,904 करोड़ रुपए जोड़कर किसानों को दिया आर्थिक सहारा

▸▸ पिछले 10 वर्षों में 1.36 करोड़ किसानों को 22,733 करोड़ रुपए की राहत सहायता

▸▸ केवल एक वर्ष में 36.74 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 10,337 करोड़ रुपए

▸▸ एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार ने अपने स्वयं के कोष से 6,904 करोड़ रुपए जोड़कर किसानों को दिया आर्थिक सहारा

गांधीनगर : मौसम में आने वाले अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण गुजरात के किसानों को पिछले एक दशक में बेमौसमी बारिश, अतिवृष्टि और चक्रवात जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे कठिन समय में राज्य सरकार ने संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए किसानों को आर्थिक समर्थन प्रदान किया है।

वर्ष 2015-16 से 2025-26 के दौरान गुजरात सरकार ने विभिन्न कृषि राहत पैकेजों के माध्यम से 1.36 करोड़ से अधिक प्रभावित किसानों को कुल 22,733 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान झेलने वाले लाखों किसानों के लिए यह सहायता संकटमोचक साबित हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में किसानों को कठिन समय में तत्काल राहत देने की परंपरा और अधिक सुदृढ़ हुई है।

सरकारी सहायता से फिर संभले देवराजभाई

सुरेंद्रनगर जिले के दसाडा तहसील के आदरियाणा गांव के किसान देवराजभाई सोलंकी के लिए पिछले वर्ष की बेमौसमी बारिश विनाश लेकर आई थी। चने की पूरी फसल बर्बाद हो जाने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था।

देवराजभाई बताते हैं, “जब मैं सुबह खेत पर पहुंचा तो पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। एक पल के लिए लगा कि अब पूरा साल कठिनाइयों में बीतेगा। लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित कृषि राहत पैकेज के तहत मिली 44,000 रुपए की सहायता हमारे परिवार के लिए आशा की किरण बन गई। हम फिर से बुवाई कर सके और खेती को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ा सके।”

देवराजभाई जैसे लाखों किसानों के लिए सरकार की यह संवेदनशीलता आशीर्वाद के रुप में साबित हुई है।

गुजरात सरकार का वर्ष 2025-26 का ऐतिहासिक कृषि राहत पैकेज

भारी वर्षा और बेमौसमी आपदाओं से हुए व्यापक फसल नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 36.74 लाख से अधिक किसानों को 10,337 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है। गुजरात के कृषि इतिहास में किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी गई यह सबसे बड़ी राहतों में से एक मानी जाती है।

धरतीपुत्रों (किसानों) के साथ मजबूती से खड़ी है गुजरात सरकार

▸▸ 2015-16 : 1.82 लाख किसानों को 279 करोड़ रुपए

▸▸ 2017-18 : 7.69 लाख किसानों को 1,706 करोड़ रुपए

▸▸ 2018-19 : 17.59 लाख किसानों को 1,678 करोड़ रुपए

▸▸ 2019-20 : 33.18 लाख किसानों को 2,489 करोड़ रुपए

▸▸ 2020-21 : 19.03 लाख किसानों को 2,906 करोड़ रुपए

▸▸ 2021-22 : 7.67 लाख किसानों को 1,240 करोड़ रुपए

▸▸ 2022-23 : 1.93 लाख किसानों को 197 करोड़ रुपए

▸▸ 2023-24 : 2.55 लाख किसानों को 410 करोड़ रुपए

▸▸ 2024-25 : 8.04 लाख किसानों को 1,491 करोड़ रुपए

▸▸ 2025-26 : 36.74 लाख किसानों को 10,337 करोड़ रुपए

किसानों के हित के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

पिछले दस वर्षों में प्रदान की गई कुल 22,733 करोड़ रुपए की सहायता में से 15,829 करोड़ रुपए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से तथा 6,904 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बजट से प्रदान किए गए हैं।

इस प्रकार; उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि प्राकृतिक आपदा की हर घड़ी में राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। परिणामस्वरूप आज गुजरात का अन्नदाता अधिक आत्मविश्वास के साथ खेती कर रहा है और उसे विश्वास है कि कठिनाई की हर घड़ी में सरकार उसके साथ है।

सुदृढ़ योजना, निवेशक अनुकूल नीतियों और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के बल पर गुजरात एक विश्वसनीय पॉलिसी-ड्रिवन स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ विलायत का विश्वस्तरीय सीपीवीसी रेजिन प्लांट गुजरात के 'मेक फॉर वर्ल्ड' विजन को देगा नई गति : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से भरूच जिले के विलायत में लुब्रिजोल और ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा स्थापित अत्याधुनिक सीपीवीसी रेजिन प्लांट का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- ▸▸ 'मेक इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर गुजरात की औद्योगिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर
- ▸▸ देश के केमिकल क्षेत्र में गुजरात की लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी उसकी औद्योगिक शक्ति का प्रतिबिंब
- ▸▸ नए निवेशों से रोजगार, एमएसएमई, सप्लाई चेन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
- ▸▸ आधुनिक टेक्नोलॉजी और वैश्विक मानकों वाला सीपीवीसी प्लांट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को भरूच जिले के विलायत में लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित अत्याधुनिक सीपीवीसी रेजिन उत्पादन प्लांट का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व अंतर्गत भारत विकास की राजनीति के नए युग में प्रवेश कर चुका है और गुजरात को उनके नेतृत्व का ढाई दशक से अधिक समय का लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने हमेशा विकासोन्मुख नीतियों, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग-अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों का विश्वास जीता है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से राज्य ने विकास के नए द्वार खोले हैं। आज पानी, रोड नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक सुविधाओं के क्षेत्र में गुजरात देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

उन्होंने कहा कि गुजरात केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को भी समान प्राथमिकता देता है। राज्य सरकार की सुदृढ़ योजना और प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप गुजरात की पहचान एक विश्वसनीय पॉलिसी-ड्रिवन स्टेट के रूप में बनी है। भरूच जिले के विलायत में स्थापित यह अत्याधुनिक सीपीवीसी रेजिन प्लांट विकास को नई दिशा देगा। गुजरात देश के केमिकल क्षेत्र में लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी रखता है और ऐसे नए उद्योग राज्य की औद्योगिक शक्ति को और अधिक मजबूत बनाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति-2026 गुजरात के विकास के इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगी। उद्योग, निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से राज्य को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को साकार करने वाली ऐसी परियोजनाएं अब 'मेक फॉर वर्ल्ड' के विजन को भी गति दे रही है। गुजरात की मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम और निवेशक-अनुकूल वातावरण के कारण अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। ऐसे बड़े औद्योगिक प्रकल्प केवल रोजगार के अवसर ही नहीं पैदा करते, बल्कि एमएसएमई इकाइयों, स्थानीय उद्योगों और सप्लाई चेन से जुड़े अनेक क्षेत्रों को भी विकास के नए अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने उद्योगों से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सस्टेनेबल और भविष्योन्मुखी विकास मॉडल अपनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करके ही सर्वांगीण और टिकाऊ विकास हासिल किया जा सकता है।

इस अवसर पर आदित्य बिड़ला समूह के ग्लोबल केमिकल्स बिजनेस हेड एवं सीईओ श्री जयंत धोबले ने कहा, "यह परियोजना ग्रासिम की मैन्युफैक्चरिंग और क्रियान्वयन क्षमता को लुब्रिजोल की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है। इसके माध्यम से भारतीय बाजार को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली सीपीवीसी सामग्री उपलब्ध होगी तथा देश में स्केलेबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विकास को गति मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि लुब्रिजोल भारत में अपने सभी उत्पादन इकाइयों में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के सर्वोच्च मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धतियों और वैश्विक सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम से कंपनी टिकाऊ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

लुब्रिजोल की सीईओ सुश्री रेबेका लिबर्ट ने लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन की विशेषताओं तथा भारत, विशेष रूप से गुजरात में अपने संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी की विशेषताओं तथा उसके उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जो गतिशीलता, स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। उन्होंने जोड़ा कि गुजरात में यह प्लांट स्थापित कर कंपनी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान देगी।

लुब्रिजोल कॉर्पोरेशन और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन उत्पादन प्लांट भारत में सीपीवीसी उत्पादन के लिए सबसे अधिक स्केलेबल और एकीकृत उत्पादन व्यवस्थाओं में से एक नई व्यवस्था के रूप में उभरा है, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्लंबिंग और पाइपिंग समाधान क्षेत्र में कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत बनाता है।

इस प्लांट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले सीपीवीसी रेजिन और कंपाउंड्स का उत्पादन किया जाएगा, जिनका उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में पाइप और फिटिंग्स के निर्माण में किया जाता है। यह एकीकृत उत्पादन ढांचा सप्लाई चेन को मजबूत करेगा तथा देश में सुरक्षित जल आपूर्ति और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास, भरूच जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती डिम्पलबेन राज, वागरा के विधायक श्री अरुणसिंह राणा, जिला कलेक्टर डॉ. नवनाथ गोव्हाणे, पुलिस अधीक्षक श्री अक्षयराज मकवाणा, जिले के अग्रणी श्री प्रकाशभाई मोदी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भावनगर रेलवे मंडल पर आयोजित 69वीं पेंशन अदालत में पेंशन संबंधी 33 मामलों का हुआ निपटारा

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर दिनांक 15 जून, 2025 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा की प्रेरणा से अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा की अध्यक्षता में "69वीं पेंशन अदालत" का सफल आयोजन किया गया। इस पेंशन अदालत में मंडल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। पेंशन भुगतान आदेश (PPO), फिक्स्ड मेडिकल एलाउन्स, पारिवारिक पेंशन, PPO में पता बदलना सहित पेंशन से जुड़े ब्रॉडगेज वर्कशॉप के 4 मामले और मंडल कार्यालय के 29 मामलों सहित कुल 33 मामलों का तत्परता एवं संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पेंशन अदालत को सफल बनाने में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, निपटारा शाखा एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके समन्वित प्रयासों से सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सका।

पेंशन से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान एवं त्वरित कार्यवाही के लिए "ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन" तथा "अखिल भारतीय रेलवे पेंशनर्स कल्याण महासंघ (All India Railway Pensioners Welfare Federation)" द्वारा प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर श्री हुबलाल जगन (वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी), श्री हरिश जनसारी (मंडल वित्त प्रबंधक), श्री संतोष कुमार वर्मा (सहायक कार्मिक अधिकारी), श्री जगदीश प्रसाद (वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी – ब्रॉडगेज वर्कशॉप) एवं श्री संजय सक्सेना (सहायक मंडल वित्त प्रबंधक) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद स्टेशन पुनर्विकास एवं अहमदाबाद-वडनगर रेलखंड का संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने आज 16 जून, 2026 को अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया तथा अहमदाबाद-वडनगर रेलखंड का व्यापक संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना के विकास तथा यात्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

महाप्रबंधक ने अहमदाबाद स्टेशन पर निर्माणाधीन साउथ ब्लॉक का दौरा कर कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 9 एवं 10 के साथ-साथ बुलेट ट्रेन स्टेशन के नीचे निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म संख्या 11 एवं 12 के कार्यों का भी अवलोकन किया।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद (DRM) श्री वेद प्रकाश ने महाप्रबंधक श्री पाण्डेय को अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण एवं आधारभूत संरचना के उन्नयन के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। मुख्य परियोजना प्रबंधक (आरएलडीए) श्री संजीव कुमार ने स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की मास्टर प्लान, विभिन्न चरणों में किए जा रहे निर्माण कार्यों तथा वर्तमान प्रगति से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित यात्री सुविधाओं, स्टेशन भवन, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की।

महाप्रबंधक ने कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु आवश्यक समन्वय बनाए रखने पर बल दिया।

इसके पश्चात श्री पाण्डेय ने अहमदाबाद-वडनगर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग्स सहित विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने रेल पथ की स्थिति, परिचालन दक्षता तथा संरक्षा मानकों का आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को संरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

वडनगर रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टेशन के रिले रूम, रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI), मास्टर केबिन, बुकिंग काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म तथा कैफेटेरिया का बारीकी से निरीक्षण किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने वडनगर स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

इस निरीक्षण के दौरान अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री वेद प्रकाश, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री संजीव कुमार सहित मुख्यालय एवं मंडल के अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में गरिमामय ढंग से मनाया गया जीएनएफसी का स्वर्ण जयंती महोत्सव

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विकसित-आत्मनिर्भर भारत 2047 के संकल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीएनएफसी द्वारा तैयार रोडमैप को तीव्र गति से साकार करने का आह्वान किया

गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में

- ▸▸ नर्मदा नगर टाउनशिप में नमो वडवन-मियावाकी फॉरेस्ट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण
- ▸▸ मुख्यमंत्री ने किया नर्मदा नगर कम्युनिटी साइंस सेंटर का लोकार्पण
- ▸▸ भरूच जिले के 50 गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए '50 विकसित गांव-विजन 2047' की महत्वाकांक्षी पहल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- ▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेशेवर दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक कुशल, पारदर्शी और लाभदायक बनाया है
- ▸▸ जीएनएफसी की पांच दशकों की सफलता गुजरात के विकास, किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में योगदान की अनन्य गाथा है
- ▸▸ जीएनएफसी ने नीम प्रोजेक्ट के जरिए 4.50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का भगीरथ कार्य किया है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार को नर्मदा नगर में राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. (जीएनएफसी) के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंतर्गत आयोजित गरिमामय समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि जीएनएफसी की पांच दशकों की सफलता गुजरात के विकास, किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में योगदान की एक शानदार गाथा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर जीएनएफसी परिवार से आह्वान किया कि वह विकसित-आत्मनिर्भर भारत 2047 के संकल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए, जीएनएफसी द्वारा तैयार मौजूदा 7 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स वाले अपने रोडमैप को 10 गुना बढ़ाकर 2047 तक 70 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तक ले जाकर साकार करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी 6 रीजन में सर्वग्राही विकास के दीर्घकालिक विजन के साथ 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात 2047' का रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन के निरंतर 12 वर्ष पूरे होने तथा जीएनएफसी की गोल्डन जुबली, दोनों अवसरों के एक साथ आने को एक सुंदर समन्वय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने इस विकास यात्रा में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अहम योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेशेवर नजरिए के साथ पीएसयू को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी के साथ ही लाभदायक भी बनाया है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक प्रदान करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ रसायन क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से हुई जीएनएफसी की स्थापना की सराहना की। उन्होंने जीएनएफसी की नीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत नीम के बीज के तेल का नीम कोटिंग के रूप में उपयोग करने तथा नीम के तेल से बने ऑर्गेनिक उत्पादों की पहल की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने इस नीम प्रोजेक्ट के तहत नीम के बीज एकत्र करने के काम में ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके लगभग 4.50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने के भगीरथ कार्य तथा भरूच जिले के 50 गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए '50 विकसित गांव-विजन 2047' की महत्वाकांक्षी पहल के लिए जीएनएफसी प्रबंधन को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीएनएफसी स्वर्ण जयंती उत्सव के एक हिस्से के तौर पर नर्मदा नगर टाउनशिप में नमो वडवन (नमो बरगद वन), मियावाकी फॉरेस्ट और ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही, उन्होंने कम्युनिटी साइंस सेंटर का उद्घाटन और जीएनएफसी की 50 वर्षों की सफलता गाथा को उजागर करने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के गोल्डन जुबली महोत्सव के अवसर पर जीएनएफसी के चेयरमैन और राज्य के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने 1991 में गुजरात में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हुई अपनी नियुक्ति के समय 'गुजरात दर्शन टूर' के तहत किए गए जीएनएफसी के दौरे की याद ताजा की। उन्होंने जीएनएफसी के गौरवपूर्ण सफर के बारे में जोर देकर बताया कि कंपनी ने अतीत के विजन की तुलना में आज काफी बड़ी प्रगति की है। कंपनी की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए उन्होंने लगभग 2,73,000 शेयर होल्डर्स, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सप्लायरों और कंपनी के नवनिर्माण में डिजाइन, कॉन्ट्रेक्ट या पसीना बहाने वाले छोटे-बड़े श्रमिकों की मेहनत की सराहना की। मुख्य सचिव सह चेयरमैन ने विजन 2047 और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप बताते हुए कहा कि गुजरात सरकार की सभी कंपनियों ने 'विजन 2047' डॉक्यूमेंट मंजूर किया है। आज जीएनएफसी के लगभग सात हजार प्रोजेक्ट्स कार्यरत हैं। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में कंपनी वैश्विक रुझानों के साथ ताल मिलाकर कंसोलिडेट, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई यानी मजबूतीकरण, विस्तार और विविधिकरण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी। साथ ही, जीएनएफसी कंपनी ने कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके प्रतीक के रूप में कंपनी ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अंतर्गत भरूच जिले के 50 गांवों को दत्तक लेकर विकसित गांव बनाने का संकल्प किया है। नई औद्योगिक नीति 2026 और आत्मनिर्भरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित की गई नई उदार औद्योगिक नीति में 25 से 30 फीसदी तक के इंटेंसिव का प्रावधान है। इसके चलते जीएनएफसी के प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी को बड़ी गति मिलेगी और @2047 के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया जा सकेगा।

जीएनएफसी के प्रबंध निदेशक श्री राजकुमार बेनिवाल ने स्वागत भाषण में जीएनएफसी की निरंतर प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जलापूर्ति मंत्री श्री ईश्वरभाई पटेल, सांसद श्री मनसुखभाई वसावा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डिंपलबेन राज, विधायक सर्वश्री रमेशभाई मिस्त्री, देवकिशोरदास स्वामी, अरुणसिंह राणा, रितेशभाई वसावा, जिला कलेक्टर डॉ. नवनाथ गव्हाणे, जीएनएफसी के स्वतंत्र निदेशक श्री अजय खरे और शेयरधारकों सहित कई अधिकारी, कर्मचारी, सप्लायर्स और अन्य आमंत्रित मौजूद रहे।

आम के छिलकों में छिपा है प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना- शहनाज़ हुसैन

गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में आम की बहार दिखाई देने लगती है। फलों का राजा कहलाने वाला आम अपने स्वाद, सुगंध और पौष्टिक गुणों के कारण हर उम्र के लोगों की पहली पसंद होता है। रसीले और मीठे आम का आनंद लेने के बाद अधिकांश लोग उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन छिलकों को हम कूड़े में डाल देते हैं, उनमें प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के अद्भुत गुण छिपे होते हैं।

आम के छिलके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और कई महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग त्वचा की देखभाल में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य उपचारों में आम के छिलकों का प्रयोग न केवल त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, बल्कि यह रासायनिक उत्पादों के उपयोग को भी कम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

यदि आप प्राकृतिक फेस पैक तैयार करना चाहते हैं तो ताजे आम के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं। आम के ताजे छिलकों को थोड़ा-सा पानी डालकर पीस लें। इसके चार चम्मच पेस्ट में दो चम्मच शहद और एक चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर लगभग दस से पंद्रह मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए ताजे पानी से चेहरा धो लें। यह पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है, रंगत निखारता है और चेहरे को प्राकृतिक चमक देता है।

आम के छिलकों को सीधे चेहरे पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताजे छिलके के अंदरूनी भाग को चेहरे पर दस से पंद्रह मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा में ताजगी आती है और थकान दूर होती है। नियमित रूप से ऐसा करने पर त्वचा अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखाई देने लगती है।

त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए आम के छिलके एक बेहतरीन प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करते हैं। इसके लिए आम के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जब वे पूरी तरह कुरकुरे हो जाएं तो उन्हें पीसकर महीन पाउडर बना लें। अब इस पाउडर में गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर गोलाकार गति में हल्की मालिश करें। लगभग दस मिनट बाद ताजे पानी से धो लें। इससे त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं, रोमछिद्र साफ होते हैं और त्वचा कोमल एवं मुलायम बनती है।

आजकल बाजार में उपलब्ध अधिकांश स्क्रब और एक्सफोलिएटिंग उत्पादों में रासायनिक तत्व होते हैं, जो संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके विपरीत आम के छिलकों से बना स्क्रब पूरी तरह प्राकृतिक होता है और त्वचा को बिना किसी दुष्प्रभाव के साफ करता है। यदि आप घरेलू स्क्रब बनाना चाहते हैं तो सूखे आम के छिलकों का पाउडर तैयार कर लें। इसमें थोड़ा-सा कॉफी पाउडर मिला दें। यदि आपकी त्वचा शुष्क है तो कुछ बूंदें नारियल तेल की भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण से चेहरे और शरीर की त्वचा को हल्के हाथों से स्क्रब करें। यह त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसमें नई चमक लाता है।

जिस दिन आप इस प्राकृतिक स्क्रब का उपयोग करें, उस दिन साबुन या किसी अन्य क्लीन्ज़र का उपयोग न करें। इससे त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी बनाए रखती है और अधिक मुलायम महसूस होती है।

गर्मियों में धूप के कारण त्वचा पर टैनिंग की समस्या आम हो जाती है। लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा का रंग गहरा पड़ जाता है और उसकी प्राकृतिक चमक कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आम के छिलके एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय साबित हो सकते हैं। आम के सूखे छिलकों का पाउडर लेकर उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चराइजिंग लोशन मिलाएं और प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। लगभग पंद्रह मिनट बाद पानी से धो लें। आम के छिलकों में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा को पोषण देते हैं और टैनिंग कम करने में सहायता करते हैं।

टैनिंग दूर करने का एक और सरल उपाय यह है कि ताजे या हल्के उबले हुए आम के छिलकों को दूध या मलाई में डुबोकर प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथों से रगड़ें। लगभग पंद्रह से बीस मिनट तक यह प्रक्रिया करने के बाद त्वचा को साफ पानी से धो लें। इससे त्वचा को गहराई से नमी मिलती है और धूप से प्रभावित भाग धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है। यदि त्वचा अधिक टैन हो गई हो तो सूखे आम के छिलकों के पाउडर में दो चम्मच दही मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। इसे प्रभावित त्वचा पर लगाकर दस मिनट तक हल्के हाथों से स्क्रब करें और फिर धो लें। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और आम के छिलकों के पोषक तत्व मिलकर त्वचा की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। आम के छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाने में भी सहायक माने जाते हैं। नियमित उपयोग से त्वचा की लोच बनी रहती है और वह अधिक स्वस्थ दिखाई देती है। साथ ही इनमें मौजूद विटामिन त्वचा को पोषण प्रदान कर प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद करते हैं। आज जब लोग प्राकृतिक और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तब आम के छिलकों का पुनः उपयोग एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। यह केवल सौंदर्य बढ़ाने का उपाय ही नहीं, बल्कि 'जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल' की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम भी है। जिन वस्तुओं को हम अनुपयोगी समझकर फेंक देते हैं, वे कई बार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। आम के छिलकों का उपयोग केवल सौंदर्य उपचार तक सीमित नहीं है। इन्हें जैविक खाद बनाने, पौधों के लिए पोषक तत्व तैयार करने तथा घरेलू बागवानी में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगली बार जब आप आम का आनंद लें, तो उसके छिलकों को कूड़ेदान में फेंकने से पहले एक बार अवश्य सोचें। ये साधारण दिखने वाले छिलके आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देने, टैनिंग कम करने, मृत कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं, उनका सही उपयोग करके हम बिना अधिक खर्च के सुंदर और स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।

लेखिका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ हैं और "हर्बल क्वीन" के नाम से लोकप्रिय हैं।

सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा को नई मजबूती, जस्टिस बीवी नागरत्ना के नेतृत्व में पुनर्गठित हुई जीएसआईसीसी

नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और लैंगिक समानता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपनी 'लैंगिक संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति' (जीएसआईसीसी) का पुनर्गठन करते हुए उसे नया स्वरूप प्रदान किया है। यह समिति कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील वातावरण विकसित करने, लैंगिक भेदभाव को रोकने तथा यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए गठित की गई है। न्यायिक व्यवस्था के भीतर सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant के निर्देश पर इस उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। नवगठित 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश B. V. Nagarathna को सौंपी गई है। उन्हें समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी और मार्गदर्शन करेंगी।

न्यायपालिका में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता को देखते हुए इस समिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि समिति का पुनर्गठन सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के लैंगिक संवेदीकरण तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित वर्ष 2013 के विनियमों के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य न्यायालय परिसर में कार्यरत महिला कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, इंटर्न, शोधार्थियों और अन्य महिला पेशेवरों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है। नई समिति में न्यायपालिका, प्रशासन और विधि क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को शामिल किया गया है। समिति के सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश Nongmeikapam Kotiswar Singh भी शामिल हैं। उनके अनुभव और न्यायिक दृष्टिकोण से समिति के कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार कावेरी को भी सदस्य बनाया गया है, जो प्रशासनिक स्तर पर समिति के कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समिति में कानूनी क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों को भी स्थान दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता Menaka Guruswamy और वरिष्ठ अधिवक्ता Liz Mathew को भी इस पैनल में शामिल किया गया है। दोनों विधि विशेषज्ञ महिलाओं के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और लैंगिक न्याय से जुड़े विषयों पर लंबे समय से सक्रिय रही हैं। उनके अनुभव से समिति को व्यापक दृष्टिकोण और व्यावहारिक सुझाव प्राप्त होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संस्थान में लैंगिक संवेदनशीलता केवल शिकायतों के निवारण तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ऐसे में जीएसआईसीसी जैसी समितियां केवल शिकायतों की जांच करने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और कर्मचारियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने का भी दायित्व निभाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट में यह समिति विशेष महत्व रखती है क्योंकि यहां देशभर से बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, शोधार्थी और कर्मचारी कार्य करते हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए आवश्यक माना जाता है। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर किसी प्रकार के उत्पीड़न, भेदभाव या असुरक्षा का सामना न करना पड़े। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र अत्यंत आवश्यक है। जीएसआईसीसी न केवल शिकायतों की सुनवाई करती है, बल्कि आवश्यकतानुसार जांच प्रक्रिया का संचालन कर उचित सिफारिशें भी देती है। इसके साथ ही समिति समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों और संवाद सत्रों का आयोजन कर कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार और लैंगिक समानता की संस्कृति को बढ़ावा देती है।